

रायपुर समेत 8 शहरों में कचरे से बनी गैस को झारसगुड़ा-नागपुर की पाइपलाइन से जोड़ेंगे

भास्कर इनसाइट

भास्कर न्यूज़/रायपुर

छत्तीसगढ़ में कचरे से गैस बनाने के लिए रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत आठ शहरों में प्लांट लगाया जा रहा है। इसके लिए गेल इंडिया और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड- बीपीसीएल जैसी बड़ी कंपनियां एक हजार करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही हैं। इसके लिए सभी स्थानों पर जमीन अलाटमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साल 2026 के अंत तक सभी प्लांट को शुरू करने का टारगेट सेट किया गया है।

बताया गया है कि बायोमास और कम्प्रेस्ड बायोगैस-सीबीजी संयंत्र स्थापित करने का एकमात्र उद्देश्य नगर निगम क्षेत्रों में कचरा-प्रबंधन को बेहतर बनाना, किसानों को अतिरिक्त आमदनी देना और ग्रीन एनर्जी का उत्पादन बढ़ाना है। बीपीसीएल द्वारा बिलासपुर में स्थापित होने वाली परियोजना को सबसे बड़ी मानी जा

कचरे से ऊर्जा बनेगी, किसानों को मिलेगा लाभ



विशेषज्ञों के मुताबिक इन संयंत्रों में नगर निगमों से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट, धान की भूसी, कृषि अवशेष और अन्य बायोमास को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इससे एक ओर शहरों में कचरे की लैंडफिल समस्या कम होगी, वहीं दूसरी ओर किसानों को उनके खेतों से निकलने वाले अवशेष का उचित दाम मिलेगा। इस परियोजनाओं के तहत बनने वाली बायो-सीएनजी गैस का उपयोग शहरों में वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाएगा। इससे डीजल और पेट्रोल पर निर्भरता घटेगी और वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी।

रही है, जिसकी लागत करीब 100 करोड़ और क्षमता लगभग 150 टन प्रतिदिन कचरा प्रसंस्करण की बताई जा रही है। जबकि रायपुर में भी जमीन चिन्हांकित कर ली गई है। बताया गया है कि इनमें से पांच प्लांट नगर निगम एमएसडब्ल्यू और शेष प्लांट

बायोमास और एमएसडब्ल्यू का मिक्स्ड है। इन सभी आठों निकायों में दोनों बड़ी कंपनियों को अपना प्लांट तैयार करने के लिए 10-10 एकड़ जमीन दी जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार इन कंपनियों को रियायती दर पर ये जमीनें उपलब्ध कराएगी।

विष्णुदेव की पहल पर बायोफ्यूल क्षेत्र में छत्तीसगढ़ बनेगा अग्रणी राज्य

रायपुर, आशीष शर्मा(पंजाब केसरी): छत्तीसगढ़ में जैव ईंधन के उत्पादन में लगभग 3500 करोड़ का निवेश हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर इस मामले में लगातार उपलब्धियाँ हासिल हो रही हैं। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित एक्सपोजे में विशेषज्ञों ने छत्तीसगढ़ में बायोफ्यूल रोड मैप विजन को लेकर जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के जैव ईंधन रोड मैप के जरिए अब बेहतर संभावनाएं नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश को बायोफ्यूल के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की पहल की जा रही है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में निजी कंपनियों ने औद्योगिक नीति पर भरोसा जताते हुए निवेश को लेकर मंशा जताई है। इनमें गेल और बीपीसीएल जैसी ओजीएमसी ने विभिन्न यूएलवी में बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्तमान में सीबीजी उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए विभिन्न स्थानों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। प्रदेश में चावल, मक्का और चने की अवशेषों का उपयोग करके बायो एथेनॉल और कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने के लिए फीड स्टॉक आधार परीक्षण किया जा रहा है। वहीं कृषि अपशिष्ट को सबस्ट्रेट के रूप में उपयोग करके एंजाइम उत्पादन परीक्षण और नए माइक्रोबियल



- बायोफ्यूल उत्पादन में छत्तीसगढ़ में हो रहा 3500 करोड़ का निवेश
- आकर्षित हो रही कंपनियां

स्ट्रेन का संवर्धन भी हो रहा है। इसी तरह बायो विमान ईंधन के क्षेत्र में भी बायोमास आधारित हाइड्रोजन उत्पादन की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव की पहल पर छत्तीसगढ़ में लगातार नए प्रयोग और परीक्षण हो रहे हैं। इस मामले में छत्तीसगढ़ जल्दी अग्रणी राज्य में शामिल हो सकता है। मुख्यमंत्री की पहल पर ही अधिशेष चावल को प्राथमिक फ्री स्तर के तौर पर उपयोग करके बायो एथेनॉल उत्पादन के लिए पहले ही मानक संचालन प्रक्रिया विकसित कर ली गई है।

जैव ईंधन के उत्पादन में 3,500 करोड़ रुपये होगा निवेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण द्वारा राजधानी रायपुर में बायोफ्यूल एण्ड बायो एनर्जी एक्सपो का आयोजन किया गया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल रोडमैप विजन 2024-29 पर आयोजित सेमीनार में बायोफ्यूल तकनीक पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के सीईओ सुमित सरकार ने बताया कि सरकार की पहल पर राज्य को बायोफ्यूल के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की पहल की जा रही है। छत्तीसगढ़ में

निजी कंपनियों ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2024-2030 के अनुरूप, लगभग 3,500 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। गैल और बीपीसीएल जैसी ओजीएमसी ने विभिन्न यूएलबी में 8 एमएसडब्ल्यू और बायोमास आधारित संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ओएनजीसी ग्रीन और एचपीसीएल ग्रीन वर्तमान में सीबीजी उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने के लिए विभिन्न स्थानों का सर्वेक्षण कर रही हैं। इस सेमीनार में

गैल के सीजीएम मोहम्मद नजीब कुरैशी और डीजीएम जितेन्द्र पाण्डेय ने छत्तीसगढ़ में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के पाइप लाइन नेटवर्क की जानकारी दी। बीपीसीएल के डीजीएम संजय ठाकुर ने छत्तीसगढ़ में कम्प्रेस बायोगैस की संभावनाओं के बारे में प्रजेंटेशन दिया। जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के डीजीएम सुशील वर्मा ने धान से कम्प्रेस बायोगैस उत्पादन के जबकि आरईवीवाय के डॉ. बनिता प्रसाद ने बायोगैस प्लांट के संचालन के बारे में जानकारी दी।